DIGITAL ADVERTISEMENT
Rs. 499/- PER MONTH
We promote your BUSINESS
Call/Whatsapp: 7789951009
TARGETED REACH | BUSINESS GROWTH | MORE CUSTOMERS | BETTER RESULTS

QKePaper.com
Free Online Daily Newspaper
अ A ह अ ठ ळ म उ प श ळ
वर्ष-02 अंक-37 शनिवार 01.08.2026 FREE EPAPER

नवनिर्मित लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृह का लोकार्पण, समाज सुधार और साहित्यिक विरासत को नई पहचान : मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई
मुंबई के भायखला पूर्व स्थित नवनिर्मित लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृह का शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भव्य समारोह में उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आधुनिक नाट्यगृह केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र नहीं होगा, बल्कि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे की सामाजिक चेतना, साहित्यिक विरासत और लोककला की परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। यह नाट्यगृह बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है।

उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े, नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े तथा राज्य सरकार और बीएमसी के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे के जीवन, साहित्य और सामाजिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मजदूरों, वंचितों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी को सामाजिक समानता तथा न्याय का संदेश देते हैं।

बैठक/समारोह की प्रमुख बातें

- ▶लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृह का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया।
- ▶नाट्यगृह का बीएमसी द्वारा आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया।
- ▶761 सीटों वाला पूर्ण वातानुकूलित आधुनिक सभागार तैयार।
- ▶अण्णाभाऊ साठे की स्मृति में विशेष स्मारक दीर्घा स्थापित।
- ▶अत्याधुनिक साउंड, लाइटिंग, मंच, ग्रीन रूम, मेकअप रूम, सीसीटीवी और अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अण्णाभाऊ साठे का साहित्य केवल मराठी समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी रचनाओं का 27 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इससे महाराष्ट्र की संस्कृति, लोककला और सामाजिक विचारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी अण्णाभाऊ साठे का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने अपनी लेखनी तथा लोककला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में कहा कि अण्णाभाऊ साठे ने अपना पूरा जीवन श्रमिकों, गरीबों और वंचित समाज के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनके साहित्य में समाज के संघर्ष, स्वाभिमान और समानता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह अत्याधुनिक नाट्यगृह कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा तथा नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा।

बीएमसी द्वारा विकसित इस आधुनिक नाट्यगृह में अत्याधुनिक ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, पूर्ण वातानुकूलित सभागार, आधुनिक मंच, ग्रीन रूम, मेकअप रूम, सीसीटीवी सुरक्षा प्रणाली, अग्निशमन व्यवस्था तथा बैकअप बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लगभग 761 दर्शकों की क्षमता वाले इस सभागार को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों, संगीत समारोहों और अन्य आयोजनों के अनुरूप तैयार किया गया है।

नाट्यगृह के भूतल पर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे को समर्पित एक विशेष स्मारक दीर्घा भी विकसित की गई है। इसमें उनकी प्रतिमा, साहित्यिक कृतियां, प्रेरक उद्धरण, लावणी और शाहिरी परंपरा से जुड़ी सामग्री, दुर्लभ चित्रों तथा सामाजिक संदेशों का प्रदर्शन किया गया है। इस दीर्घा का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को अण्णाभाऊ साठे के जीवन, साहित्य और सामाजिक आंदोलन से परिचित कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और आधुनिक सांस्कृतिक अधोसंरचना के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कलाकारों से इस मंच का उपयोग समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने तथा मराठी साहित्य और लोकसंस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नाट्यगृह मुंबई की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा तथा सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रमुख केंद्र बनेगा।

जूडो में भारत को 2 गोल्ड मेडल, साइकिल मैकेनिक की बेटी अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने ग्लासगो में रचा इतिहास

नई दिल्ली
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 9वां दिन भारत के लिए खास है। भारत ने कई मेडल पक्के किए। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रच दिया। दोनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अस्मिता ने महिलाओं के 48kg वेट क्लास में कनाडा की हेइडी क्वाच को हराया।
वहीं हर्ष ने पुरुषों के 60kg मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ काट्ज को मात दी। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के अब 19 मेडल हो गए हैं। इनमें 5 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
आर्थिक चुनौतियों का सामना किया अस्मिता डे दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया की रहने वाली एक भारतीय जूडोका हैं। एक साधारण परिवार में जन्मीं अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक हैं। उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए जूडो को अपनाया। एक बयान के अनुसार, शुरुआत में उन्होंने एथलेटिक्स (800 मीटर) में हिस्सा लिया था, लेकिन फिर उनके पहले कोच ने उन्हें जूडो से परिचित कराया, जिसके बाद 2015 में वह त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में शामिल हो गईं।

नेशनल स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से 2018 में उन्हें SAI रीजनल सेंटर, भोपाल (NCOE) में जगह मिली और तब से वह NCOE भोपाल में ट्रेनिंग कर रही हैं। अस्मिता ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। इस तरह उन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की प्रमुख जूडोका के तौर पर अपनी पहचान बनाई है।

हर्ष सिंह के बारे में
हर्ष सिंह भारत के एक बेहतरीन जूडोका हैं। वह पुरुषों की 60 किलोग्राम से कम वजन वाली कैटेगरी में खेलते हैं। हर्ष ने घरेलू जूडो सर्किट में तेजी से अपनी पहचान एक दमदार जूडोका के तौर पर बनाई है और वे लगातार देश के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ टॉप सम्मान के लिए मुकाबला करते रहे हैं। नेशनल रैंकिंग और सिलेक्शन ट्रायल्स में लगातार शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें ग्लोबल IJF वर्ल्ड टूर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, जहां वे टोक्यो ग्रैंड स्लैम, एशियन चैंपियनशिप और ग्रांड प्रिक्स जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

बिना सहमति फसल ;ण नवीनीकरण का आरोप, कर्जमाफी से वंचित किसानों ने जांच की मांग उठाई

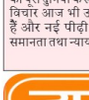

छत्रपति संभाजीनगर छत्रपति संभाजीनगर जिले के मंठा तालुका में किसानों की सहमति के बिना फसल ऋण (क्रॉप लोन) का नवीनीकरण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि बैंकों ने किसानों की मांग या लिखित अनुमति के बिना ही ऋण का नवीनीकरण कर दिया, जिसके कारण कई पात्र किसान राज्य सरकार की कर्जमाफी योजना के लाभ से वंचित रह गए। मामले को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

माळतोंडी गांव के किसान उद्धव ताठे के पुत्र आसाराम ताठे ने जिला उपनिबंधक के पास शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान उनके पिता के फसल ऋण का नवीनीकरण बिना जानकारी और सहमति के कर दिया गया। बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 2020 में लगभग 24,700 रुपये का फसल ऋण दिया गया था, जिसे बाद में सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से स्वतः नवीनीकृत कर दिया गया। इससे किसान को कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल सका और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

जिला उपनिबंधक कार्यालय ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। वहीं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की मंठा शाखा ने भी शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच जारी होने की जानकारी दी है। हालांकि बैंक प्रबंधन का दावा है कि नवीनीकरण सेवा सहकारी संस्था द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर किया गया था, जबकि किसान इस दावे को गलत बताते हुए अपनी सहमति के बिना कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा रहे हैं।

इस बीच क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि कुछ अन्य बैंकों द्वारा भी इसी प्रकार कई किसानों के फसल ऋण का स्वतः नवीनीकरण किया गया है। किसान संगठनों ने सभी ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर प्रभावित किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ देने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बैंक अधिकारियों की मनमानी का आर्थिक बोझ किसानों पर नहीं डाला जाना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

अभिजीत दीपके ने भी मांगा अमित शाह का इस्तीफा, कहा- छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिया होगा!

एसटी स्मार्ट कार्ड की समय-सीमा १ सितंबर तक बढ़ी, महिला और वरिष्ठ यात्रियों को बड़ी राहत

मुंबई
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एमएसआरटीसी) ने रियायती यात्रा के लिए अनिवार्य किए गए एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) स्मार्ट कार्ड की समय-सीमा बढ़ाकर 1 सितंबर 2026 कर दी है। पहले यह कार्ड 1 अगस्त से अनिवार्य किया जाना था, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अब तक स्मार्ट कार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री तथा एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने बताया कि पात्र यात्रियों को तकनीकी या प्रक्रियागत देरी के कारण किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यह अतिरिक्त समय दिया गया है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के 'अमृत ज्येष्ठ' नागरिकों को एसटी बसों में निःशुल्क यात्रा, जबकि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। इन रियायतों को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड लागू किया जा रहा है। हालांकि, पंजीकरण कराने के बावजूद अनेक पात्र यात्रियों को अभी तक कार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके चलते सरकार ने इसकी अनिवार्यता को एक माह के लिए टाल दिया है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के 'अमृत ज्येष्ठ' नागरिकों को एसटी बसों में निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्मार्ट कार्ड व्यवस्था से यात्रा रियायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी, नकदी रहित टिकट प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने सभी पात्र यात्रियों से 1 सितंबर से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में रियायती यात्रा का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे।

अभिजीत दीपके का दावाकृभाजपा में शामिल होने का मिला प्रस्ताव, आंदोलन वापस लेने के लिए बनाया गया दबाव

छत्रपति संभाजीनगर
छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरा और सीजेपी (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन पर आंदोलन वापस लेने का दबाव बनाया गया और उन्हें तथा उनके परिवार को गंभीर धमकियां भी मिलीं। दीपके ने कहा कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार किया क्योंकि उनका आंदोलन छात्रों के हितों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए था, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। एक पत्रकार वार्ता में दीपके ने कहा कि यदि उनके आंदोलन को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप सही हैं, तो यह देश की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता होगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि ऐसे आरोपों के ठोस प्रमाण हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने दोहराया कि उनका आंदोलन पूरी तरह छात्रों के सहयोग और जनसमर्थन से संचालित हुआ तथा इसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों को न्याय दिलाना था। दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा में शामिल होने से इनकार करने के बाद उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाने की धमकियां दी गईं। उनका कहना है कि आंदोलन समाप्त कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव के आगे झुकने से

इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी छात्रों पर कार्रवाई जारी रही, जिससे युवाओं में असंतोष बना हुआ है। वहीं, भाजपा की ओर से उनके आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

78,215 किसानों का आधार प्रमाणीकरण लंबित, योजनाओं के लाभ पर संकट के बादल

जालना
जालना जिले में कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण (आधार ऑथेंटिकेशन) की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। जिले के कुल 78,215 किसानों का आधार प्रमाणीकरण लंबित होने से उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान और कृषि संबंधी लाभ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी पात्र किसानों से जल्द से जल्द आधार प्रमाणीकरण पूरा कराने की अपील की है। हाल के राज्य स्तरीय निर्देशों के अनुसार कई किसान हितैषी योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।

कृषि विभाग के अनुसार, जिन किसानों का आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनके आवेदन लंबित रह सकते हैं। इसके चलते फसल सहायता, कृषि अनुदान, बीमा तथा अन्य सरकारी लाभों के वितरण में बाधा आने की आशंका है। इसलिए संबंधित विभाग ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाकर किसानों को आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जागरूक कर रहा है। इसलिए सभी किसानों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है।
कृषि अधिकारियों का कहना है कि आधार प्रमाणीकरण पूरा होने से लाभार्थियों की

सही पहचान सुनिश्चित होगी, योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी सहायता सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगी। प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों और कृषि कर्मियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने तथा प्रत्येक किसान तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

आवास योजना की राशि घर बनाने में ही खर्च करें, कर्ज चुकाने में नहीं

रमाई आवास योजना की पहली किस्त 25 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, पात्र लाभार्थियों को समय पर निधि देने के निर्देश

छत्रपति संभाजीनगर
छत्रपति संभाजीनगर में रमाई आवास योजना के तहत प्रथम किस्त वितरण समारोह के दौरान जिले के पालकमंत्री संजय शिरसाट ने लाभार्थियों से अपील की कि आवास योजना की किस्त का उपयोग केवल घर निर्माण के लिए करें, उसे पुराने कर्ज या उधार चुकाने में खर्च न करें। उन्होंने कहा कि सरकार पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से ढाई लाख रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। यदि यह राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई तो घर निर्माण अधूरा रह जाएगा और योजना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कार्यक्रम में ओबीसी कल्याण मंत्री

अतुल सावे, महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, नगर निगम आयुक्त अमोल येडगे सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संजय शिरसाट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि आवास योजना के कार्यों में तेजी लाई जाए तथा पात्र लाभार्थियों को समय पर किस्त उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि पहले आवास निर्माण की पहली किस्त 25 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है, जिससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी।

पालकमंत्री ने कहा कि पूर्व में योजना में फर्जी लाभार्थियों को शामिल किए जाने के आरोप लगे थे, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद योजना को क्लीन चिट मिली। उन्होंने प्रशासन को लाभार्थियों की सहायता के लिए विशेष कक्ष स्थापित करने, आवेदन भरने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा प्रत्येक माह लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री अतुल सावे ने लाभार्थी चयन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने, एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने तथा पात्र परिवारों को शीघ्र निधि उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पात्र आवेदकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी।

हिंगोली में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित, 30 में से 27 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज

हिंगोली
हिंगोली जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। लगातार वर्षा के कारण जिले की नदियां और नाले उफान पर आ गए तथा 30 में से 27 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार जिले में औसतन 103.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 145 मिमी बारिश हिंगोली तालुका में हुई, जबकि सबसे कम 70.4 मिमी वर्षा वसमत तालुका में दर्ज की गई।

भारी बारिश के कारण कयाधू नदी पहली बार इस मानसून में पूरे उफान के साथ बहने लगी। सेनगांव तालुका के रामप्रसाद नगर में घोरदरी नदी के तेज बहाव में एक

कार बह गई, हालांकि उसमें सवार चारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं, कलमनुरी तालुका के सोडेगांव पुल तथा हिंगोली तालुका के समगा पुल पर नदी का पानी बहने से कुछ समय के लिए कई गांवों का संपर्क टूट गया। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी और लोगों से नदी-नालों के पास न जाने की अपील की।

लगातार हुई वर्षा से खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब डेढ़ महीने की वर्षा कमी के बाद हुई इस तेज बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव और कुछ ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित रहा। जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है।

लातूर जिला अस्पताल को 500 बेड का बनाने की मांग, स्वास्थ्य मंत्री से मिले विधायक अभिमन्यु पवार

लातूर
लातूर जिले में लगातार बढ़ रहे मरीजों के दबाव को देखते हुए जिला अस्पताल को 500 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल में विकसित करने की मांग तेज हो गई है। विधायक अभिमन्यु पवार ने मुंबई में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर से मुलाकात कर जिला अस्पताल के विस्तार और आवश्यक सुविधाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। इस संबंध में मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लातूर के प्रभारी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले भी मौजूद रहे। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक पवार ने बताया कि लातूर शहर की बढ़ती आबादी और जिलेभर से आने वाले मरीजों के

कारण वर्तमान 100 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं रह गया है। उन्होंने मौजूदा अस्पताल भवन में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं शामिल करने, अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने तथा शेष 400 बिस्तरों के निर्माण के लिए एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) निधि से प्रस्ताव स्वीकृत करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर विस्तृत अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में औसा उपजिला अस्पताल को पूर्ण क्षमता से संचालित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ तथा समूह 'अ' से 'ड' तक के कर्मचारियों के 69 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। मंत्री ने इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तत्काल भेजने के निर्देश दिए। विधायक पवार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए तालुका स्वास्थ्य अधिकारी (टीएचओ) के पद पर अनुभवी एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति जारी रखने की भी मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।